श्री सभापति: आप पहले उन्हें बोलने दो ।

श्रीमती सरोज दुबे: यह आदिवासियों का सवाल है ।

श्री सभापति: ठीक है प्रश्न संख्या 587 ।

कुमारी मैबल रिबैलो: सर, मुझे एक सप्लीमेंटरी पूछना था।

श्री सभापति: उन्होंने पहली बात उत्तर दिया है । उनका मेडन रिप्लाई है ।

श्री प्रेम गुप्ता: मेडन रिप्लाई है, इसलिए उन्हें ग्रेस मिली है ।

Gas-based Fertilizer Units

587. DR. T.SUBBARAMI REDDY :††
DR. M.N. DAS:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have prepared a list of gas-based fertilizer units which will be encouraged to raise production capacity;

(b) if so, the number of fertilizer units that have been allowed to raise the production capacity;

(c) whether any incentives will be provided to these fertilizer units; and

(d) if so, to what extent this decision will help to contain the subsidy outgo to production units thriving on Gold-Plating and reward the efficient play ers in the domestic market ?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SUKHDEV SINGH DHINDSA) :(a) to (d) A Statement is laid on the table of The House.

Statement

(a) to (c) The New Pricing scheme for urea units, which has come into effect from 1 -4-2003, envisages that there will henceforth be no capping on production of urea by the units. Under the Scheme, there shall neither be any reimbursement of the investment made by a unit for improvement in operations nor any mopping up of gains of the units as a result of operational efficiency. These principles are applicable uniformly to all the units.

(d) The issue of hidden capacity leading to undue gains by some of the urea units, which is commonly called as 'Gold Plating', has already been addressed and a communication dated 4.6.2002 on reassessed capacity of 20 urea units has come into effect from 1-4-2000.

††The question was actually asked on the floor of the House by Dr. T. Subbarami Reddy

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Mr. Chairman, Sir, I want to draw your attention to the reply given by the hon. Minister. My question is, whether the Government have prepared a list of gas-based fertilizer units which will be encouraged to raise the production capacity. The reply does not deal at all with the gas-based pioneering fertilizer projects. The idea is, the gas-based projects are very economical; the cost per tonne is Rs. 5,000/-, whereas in a fuel-based project it is Rs. 11,000/-. Perhaps, by mistake, the reply is given by the Government in a different way. In the reply, it is stated: "The New Pricing scheme for urea units, which has come into effect from 1-4-2003— " Like that, it is given. 1 want to know from the hon. Minister what is the plan to replace, in future, the oil-based fertilizer projects with the gas-based fertilizer projects; how many projects have been identified; and whether he is planning to have any gas-based projects in Andhra Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh.

श्री सुखदेव सिंह ढ़िडसाः मैंने जो जवाब दिया है, उसमें हमने जो नयी पॉलिसी बनाई है वह ग्रुप बेस्ड़ पॉलिसी बनायी है । उससे पहले वह यूनिट बेस्ड़ थी। हमने तीन साल का समय उसको चेंज करने के लिए दिया है । जो नाफ्था बेस्ड है और मिक्स्ड फ्यूल के हैं, उनको वे तीन साल के अंदर चेंज करेंगे। हमने तीन साल का टाइम दिया है ताकि वे उसको चेंज कर सकें । इसलिए हमने ग्रुप बेस्ड बनाया है । उसमें आटोमैटीकली जो गैस बेस्ड प्लांट्स हैं, उस पालिसी में मैनेडेट है कि गवर्नमेंट उससे, जो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा पैदा करेगा, तो 15 परसेंट ले सकती है, और किसी से नहीं ले सकते, न नाफ्था बेस्ड से और न किसी दूसरे से । इसलिए यह नयी पॉलिसी उसी को ठीक करने के लिए बनायी गयी है ।

DR. T. SUBBARAMI REDDY : Mr. Chairman, Sir, now, a subsidy of Rs.50,000 crores is being given for fertilizers. In India, we have 50 per cent gas-based projects, 30 per cent oil-based projects and 20 per cent others. If the Government does not take pains and change the policy, who will change it? What is the role of the Government? The Government should take pains, Sir. If it concentrates more on gas- based projects, he can put Rs.5,000/- per tonne. It means that the Government can also save the subsidy money. My question is whether the Government is going to make any efforts to give more priority to gas based projects in India and consider, if anyone comes forward with a proposal. Do you want to replace the existing projects with gas-based projects? What is your role? What are your plans to reduce the subsidy expenditure and help the nation?

श्री सुखदेव सिंह ढ़िडसाः सर, आपको भी मालूम है कि अभी तो इतनी गैस है नहीं और जो गैस-बेस्ड हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी पूरी गैस नहीं मिल रही है , इसलिए दूसरे fuel से उनको

चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ इस पॉलिसी का मकसद यह है कि 2005-06 तक जब गैस आ जाएगी, उस वक्त वे अपने आपको गैस-बेस्ड बना लेंगे और इसका फायदा उनको भी होगा और गवर्नमेंट को भी होगा।

DR. M. N. DAS : Sir, the hon. Minister was pleased to inform the House that a new scheme has been put into effect from 1 st April, this year. I would like to know from the hon. Minister whether his Ministry has taken into consideration the poor and marginal farmers, while preparing this new scheme. Will they benefit from this scheme? If they don't benefit, is it advftable and desirable to withdraw the system of subsidy in respect of urea?

श्री सुखदेव सिंह ढ़िंडसाः चेयरमैन सर, यह कई बार यहां डिसकस हुआ है कि किसान को डायरेक्ट सबसिडी दी जाए । हमारी पिछली बजट स्पीच में भी मिनिस्टर साहब ने यह कहा था। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने और हमने भी सोचा है कि किसान को डायरेक्ट सबसिडी कैसे दी जाए लेकिन वह इसलिए नहीं देते क्योंकि जो छोटा किसान है, उसके पास वह पहुंचती नहीं है । यह किसी वर्ग के किसानों के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गो के किसानों के लि एक जैसी पॉलिसी है और एक ही रेट पर उनको यह मिलती रहेगी और अभी भी मिल रही है ।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Mr. Chairman, Sir, this supplementary arises out of the reply given to the question. In the reply, he has stated that the capping on production has been removed. In that case, urea will be available in abundant quantities hereafter. A proper mix of fertilisers is a must for the proper development of agriculture as well as for proper keeping of the land. Suppose one particular fertilizer alone comes to the market in abundant quantities, I feel it will be applied in a skewed manner, not in the proper mix. I would like to know from the hon. Minister whether he has taken this into consideration, while taking this decision. If only one particular fertiliser is going to be used by the farmers, will it not affect the development of agriculture as well as land, in future?

श्री सुखदेव सिंह ढ़िंडसाः चेयरमैन सर, पहले जब दूसरे फर्टिलाइज़र को डीकंट्रोल किया गया तो ऑनरेबल मैम्बर ने जैसा कहा वैसा ही हुआ कि डी.ए.पी. और दूसरे फर्टिलाइज़र का यूज़ कम हो गया । इसलिए दोबारा स्कीम आई। दूसरों को भी चाहे डी.ए.पी. हो या एम.ओ.पी. हो, उन पर भी कंसेशन गवर्नमेंट देती है लेकिन वे कंट्रोल में नहीं हैं, उनको कंसेशन देते हैं, इसलिए कि उनका यूज़ भी जारी रहे।

DR. ARUN KUMAR SARMA: Mr. Chairman. Sir, the hon. Minister, in his reply, has categorised all gas-based fertiliser units in one go. I would like to know from him: What is his Ministry planning to support the Brahmaputra Valley Fertiliser Corporation for its expansion and viability, since it is a newly-formed

company? I would also like to know from the hon. Minister whether he would revise the wages, which he had committed when he visited the company last time.

श्री सुखदेव सिंह ढिडसाः सर, इसमें वेज रिवीज़न का प्रश्न तो नहीं आता है लेकिन ऑनरेबल मैम्बर को मालूम है कि मैं खुद वहां पर गया हूं। हमने खुद अलग से एक कंपनी बनाकर शुरु की है। अभी तो उसका पूरा प्रोडक्शन आया भी नहीं है, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे।

श्री प्रेम गुप्ताः मान्यवर, यूरिया को लेकर इम्पोर्ट और प्राइसिंग पॉलिसी अपने आप में बड़ा भारी चक्र है। आपको यह जानकर अजीब लगेगा कि 1-4-2002 को जो प्राइसिंग पॉलिसी सेटल हुई, उसमें यूरिया 5,000 रुपए से ले कर 14,000 रुपए तक की रैंज में खरीदा गया। उसका कारण यह है कि जो इनएफिशिएंट यूनिट्स थे, उनसे हायर प्राइस में खरीदा जाता था। जो एफिशिएंट यूनिट्स थीं उनसे लोअर प्राइस में खरीदा जाता था। माननीय मंत्री जी का पहले भी कई बार क्वेश्चन आया है, यह उनके नोटिस में डाला है , मैंने कई बार लेटर भी लिखा है। सभापति जी, आप यह देखिए कि एक तरीके से यह यूनिट्स को सब्सिडी दी जाती थी, न किसानों को। इन्होंने अभी जो 1-4-2003 को किया है वह पहले क्यों नहीं किया? सभापति जी , एक सवाल और उठता है और वह यह है कि अभी इन्होंने ग्रुपिंग में कुछ यूनिट्स ऐसी हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जैसे एल.एस.एच.एस. बेस्ड यूनिट है, इसमें आठ हजार की लोएस्ट प्राइस है और चौदह हजार, पांच सौ चोरानवें की एक यूनिट है, उससे आप हायर प्राइस में खरीद रहे हैं, आप किस खुशी में इस यूनिट को छह हजार रुपए पर मीट्रीक टन दे रहे हैं आप किसान का नाम ले रहे हैं, आप तो खुद किसान हैं, क्या आप इन सब चीजों को नहीं समझते? आपको यह चक्कर इतनी देर से क्यों समझ में आया? इसके पीछे क्या राज है?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसाः सभापति जी, यह मैं नहीं कह सकता क्योंकि ऐसा पहली सरकारों में होता था। प्रधानमंत्री ...**(व्यवधान)**....

श्री प्रेम गुप्ताः जो पहली सरकारों में होता था वह आपकी सरकारों में क्यों हुआ? ...**(व्यवधान)**....

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसाः मैं यही कह रहा हूं...**(व्यवधान)**....

श्री प्रेम गुप्ता: आप पहली सरकारों की बात कर रहे हैं, अपनी सरकार की बात कीजिए।

श्री सभापतिः इन्हें बोलने दीजिए।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसाः आप जवाब तो सुन लीजिए। सभापति जी, प्रधानमंत्री ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया। इसकी मीटिंग में हम खुद हैरान थे। एक दफा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की

मीटिंग चल रही थी, फाइनेंस मिनिस्टर श्री यशवंत सिन्ह जी कहने लगे कि जिसने यह पॉलिसी बनाई है उसे पद्म श्री देनी चाहिए । पुरानी पॉलिसी में ऐसा था कि हर यूनिट से एक-एक चीज के लिए जैसे फीड स्टाक, फ्यूल, परचेज पावर, वाटर हर चीज की कास्ट वे लेते थे । ग्रुप ऑफ मिनिटर्स ने यह रिकमेंड किया कि जो गैस बेस्ड है, इसमें से एक तो छह हजार पर मीट्रिक बनाती है, दूसरी आठ हजार बनाती है इसलिए इसमें से सात हजार की एवरेज ले ली। नाफ्था बेस्ड का एक ग्रुप बना दिया ...(**व्यवधान**)....

श्री प्रेम गुप्ताः मिनिस्टर साहब, मैं कुछ और बात कर रहा हूं, आप दूसरी बात कह रहे हैं। मैं यह पूछ रहा हूं कि आपने हायर प्राइस क्यों पे की ? जब एफिशिएंट यूनिट्स से देश में यूरिया अवेलेबल था तो आपने हायर प्राइस क्यों पे की? जब पांच हजार रुपए टन में यूरिया अवेलेबल था तो आपने पंद्रह हजार रुपए टन में यूरिया क्यों खरीदा? आप फार्मर को सब्सिडी दे रहे थे या इंडस्ट्री को दे रहे थे? मैंने सवाल कुछ पूछा और आपने उसका जवाब कुछ और दिया? आपने कहा कि मैं देख रहा हूं ...(**व्यवधान**).... उसके बाद... जब अखबारों में, मैंग्जीन्स में यह इश्यू आया ...(**व्यवधान**).... सभापति जी, इन लोगों ने बड़ा भारी स्कैण्डल किया है ...(**व्यवधान**).... आपने किया क्या है, यह बताइए? ...(**व्यवधान**).... आपने कहा कि यशवंत सिन्हा ने यह कहा...(**व्यवधान**).... वह किया ...(**व्यवधान**).... आप हिस्टोरीकल चीज बता रहे हैं ...(**व्यवधान**).... आप यह क्यों नही बताते कि आपने तीन सालों में क्या किया?

श्री सभापतिः गुप्ता जी बैठिए, बैठिए।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसाः सभापति जी, ऐसा है कि जो नाफ्था बेस्ट यूनिट्स हैं, अगर आज हम उन्हें बंद कर दें तो हमें यूरिया नहीं मिलेगा । इसीलिए जो गैस बेस्ड हैं नहीं उन्हें तीन साल का टाइम दिया है । गैस मिलती नहीं है । इतनी गैस नहीं मिलती जिससे हम गैस बेस्ड दे सकें । इसीलिए पॉलिसी बनाई है कि जो ज्यादा कीमत पर पैदा करते हैं उसे आहिस्ता-आहिस्ता कम करके गैस बेस्ड पर लाएं ताकि तीन साल में हमारी सब्सिडी कम हो जाए ।

श्री प्रेम गुप्ता: सभापति जी, गैस बेस्ड पर पांच से छह हजार रुपए टन पर यूरिया मिलता है ...(**व्यवधान**).... आप इस तरह से यूरिया ...(**व्यवधान**).... आप कैसे गैस का इम्पोर्ट अलाऊ कर सकते ...(**व्यवधान**).... मान्यवार, नाफ्था में दस हजार से लेकर पंद्रह हजार तक का प्राइस है ...(**व्यवधान**)....

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: ...(**व्यवधान**).... एक दस हजार की यूनिट है ।

श्री सभापतिः बस हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ।

---

* 588 [The questioner (Miss Pramila Bohidar) was absent. For answer *vide* page 42-43.. Infra]

588[The questioner (Shri B P. Apte) was absent. For answer *vide* page 43 Infra.]